REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2025

रीवा जिले में युवाओं के डिजिटल उद्यमिता और स्वरोजगार की संभावनाएँ (रीवा जिले के विशेष सन्दर्भ में)

ऊषा पटेल
शोधार्थी समाजशास्त्र
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. रचना श्रीवास्तव
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

इस शोध का उद्देश्य रीवा जिले में युवाओं के डिजिटल उद्यमिता और स्वरोजगार की संभावनाओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। डिजिटल इंडिया और अन्य सरकारी पहलों ने ग्रामीण और अर्ध–शहरी युवाओं में डिजिटल कौशल, उद्यमिता की सोच और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाएँ और प्रशिक्षण केंद्र युवाओं के जीवन और समाज पर प्रभाव डाल रहे हैं। शोध पद्धति के रूप में सर्वेक्षण, साक्षात्कार और द्वितीयक डेटा विश्लेषण का उपयोग किया गया। रीवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं का सर्वेक्षण करके उनकी डिजिटल गतिविधियों, स्वरोजगार के प्रकार और सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि युवाओं ने ई–कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और तकनीकी स्टार्टअप्स जैसे स्वरोजगार के अवसर अपनाए हैं। डिजिटल उद्यमिता ने युवाओं में आत्मनिर्भरता, सामाजिक पहचान और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं की असमान पहुँच, डिजिटल मार्केटिंग एवं वित्तीय प्रबंधन में कमी और प्रारंभिक पूंजी की कमी जैसी चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं। सरकारी पहल जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने युवाओं को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान कर इन बाधाओं को कम करने में योगदान दिया है।

मुख्य शब्द – डिजिटल उद्यमिता, स्वरोजगार, डिजिटल कौशल, युवाओं का सशक्तिकरण एवं डिजिटल इंडिया।

प्रस्तावना –

आज के युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने केवल जीवन की दैनिक गतिविधियों को ही

नहीं बदला है, बल्कि रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक सहभागिता के तरीके भी पूरी तरह बदल दिए हैं। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना इसी परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटली सशक्त बनाना, सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों तक पहुँचाना और युवाओं में डिजिटल कौशल विकसित करना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र, ई–गवर्नेंस सेवाएँ, ऑनलाइन बैंकिंग और ई–कॉमर्स जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से युवाओं को न केवल स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, बल्कि वे अपनी क्षमता के अनुसार नए व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं।

रीवा जिला, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ अधिकांश युवा पारंपरिक रोजगार और कृषि पर निर्भर हैं। पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहुँच ने रीवा के युवाओं के सामने डिजिटल स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर खोले हैं। उदाहरण के लिए, ई–कॉमर्स के माध्यम से उत्पाद बेचने, सोशल मीडिया के जरिये मार्केटिंग करने और तकनीकी स्टार्टअप्स शुरू करने जैसे अवसर अब ग्रामीण और अर्ध–शहरी युवाओं के लिए सुलभ हो गए हैं।

डिजिटल उद्यमिता युवाओं में आत्मनिर्भरता, सामाजिक पहचान और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार और समुदाय के स्तर पर भी सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाता है। उदाहरण के लिए, डिजिटल स्वरोजगार से परिवार की आय में वृद्धि होती है, शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलता है और युवाओं में नवाचार और उद्यमिता की मानसिकता विकसित होती है।

डिजिटल उद्यमिता की दिशा में कई चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। रीवा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं की पहुँच सीमित है, डिजिटल साक्षरता का स्तर अभी भी कम है और वित्तीय संसाधनों की कमी युवा उद्यमियों के लिए बाधा उत्पन्न करती है। इसके अलावा, डिजिटल मार्केटिंग, व्यवसाय प्रबंधन और तकनीकी प्रशिक्षण की कमी भी युवाओं को डिजिटल व्यवसाय शुरू करने में सीमित करती है। इसके बावजूद, डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने युवाओं को नए अवसरों का लाभ उठाने और स्वरोजगार बढ़ाने में मदद की है। डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी योजनाएँ युवाओं को व्यवसाय शुरू करने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और अपने उत्पाद या सेवाओं का बाजार तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

शोध के उद्देश्य –

- रीवा जिले के युवाओं में डिजिटल कौशल और उद्यमिता की स्थिति का मूल्यांकन।
- युवाओं द्वारा अपनाए गए डिजिटल स्वरोजगार के प्रकारों का अध्ययन।
- डिजिटल उद्यमिता से युवाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन में आए परिवर्तन।
- डिजिटल स्वरोजगार के विकास में आने वाली प्रमुख समस्याओं और बाधाओं की पहचान।
- डिजिटल इंडिया और अन्य सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन।

विश्लेषण –

1. डिजिटल कौशल और प्रशिक्षण – रीवा जिले के युवाओं में डिजिटल कौशल का स्तर हाल के वर्षों में लगातार बढ़ा है। सर्वेक्षण से यह पता चला कि अधिकांश युवाओं ने मोबाइल फोन और कंप्यूटर का उपयोग करना सीख लिया है और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने तथा संचार करने में सक्षम हैं। हालांकि, यह प्राथमिक कौशल केवल डिजिटल उपकरणों का परिचय प्रदान करता है, जबकि डिजिटल उद्यमिता के लिए अधिक जटिल और विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने

के लिए आवश्यक डिजिटल मार्केटिंग, ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग, वेबसाइट और एप्लिकेशन डेवलपमेंट, सोशल मीडिया प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन जैसे कौशल प्राथमिक ज्ञान से बहुत आगे हैं।

डिजिटल इंडिया की पहल ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिले में स्थापित डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र, आईटी साक्षरता कार्यक्रम और ऑनलाइन कोर्सेस ने युवाओं को न केवल तकनीकी कौशल सिखाया है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक भी किया है। प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को व्यवसाय मॉडल, मार्केटिंग रणनीतियों और वित्तीय प्रबंधन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन कोर्स और ट्यूटोरियल ने युवाओं को घर बैठे सीखने का अवसर प्रदान किया है, जिससे ग्रामीण और अर्ध–शहरी युवाओं में कौशल विकास में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, प्रशिक्षण की पहुँच और गुणवत्ता में असमानता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अधिकांश ग्रामीण युवाओं के पास प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुँच आसान नहीं है। साथ ही, कई युवाओं को डिजिटल उद्यमिता के लिए प्रेरित करने और उन्हें मार्गदर्शन देने वाले मेंटर की कमी है। इन बाधाओं के बावजूद, प्रशिक्षित युवा धीरे–धीरे डिजिटल व्यवसायों और स्वरोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं।

2. डिजिटल स्वरोजगार के प्रकार– रीवा जिले के युवाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कई प्रकार के स्वरोजगार अवसर अपनाए हैं। सर्वेक्षण और साक्षात्कार से यह स्पष्ट हुआ कि युवाओं के डिजिटल स्वरोजगार के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं–

ई–कॉमस – सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटप्लेस (जैसे–अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो) के माध्यम से उत्पाद बिक्री करना रीवा के युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रहा है। युवा हैंडीक्राफ्ट, कृषि उत्पाद, घरेलू खाद्य पदार्थ और कपड़े जैसे उत्पाद बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। ई–कॉमर्स ने युवा उद्यमियों को व्यापक बाजार तक पहुँच प्रदान की है और पारंपरिक व्यवसाय मॉडल पर निर्भरता को कम किया है।

एप डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स – कुछ तकनीकी शिक्षित युवा मोबाइल एप्लिकेशन, वेबसाइट और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी सक्रिय हुए हैं। ये युवा विशेष रूप से शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में तकनीकी सहायता, शिक्षा और व्यवसाय सेवाओं के लिए डिजिटल समाधान प्रदान कर रहे हैं। हालांकि यह स्वरोजगार अपेक्षाकृत उच्च कौशल और पूंजी की माँग करता है, लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव अधिक गहरे हैं। इन स्वरोजगार प्रकारों से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने रीवा जिले के युवाओं के लिए पारंपरिक सीमाओं को पार करने और नए अवसरों की खोज करने के मार्ग खोल दिए हैं।

3. सामाजिक और आर्थिक प्रभाव – डिजिटल उद्यमिता ने रीवा जिले के युवाओं के जीवन में सकारात्मक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाए हैं। सबसे पहले, डिजिटल स्वरोजगार ने युवाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाई है। युवाओं ने पारंपरिक रोजगार की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता और आय के अवसर प्राप्त किए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, युवा अपनी कमाई से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं और घर–परिवार के निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावशाली बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल उद्यमिता ने सामाजिक पहचान और आत्म–सम्मान को भी बढ़ाया है। ऑनलाइन व्यवसायों और स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं ने समाज में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया है। कई युवाओं ने अपने व्यवसाय से स्थानीय रोजगार उत्पन्न किया है, जिससे ग्रामीण और अर्ध–शहरी समाज में रोजगार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। डिजिटल स्वरोजगार ने शिक्षा और कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया है। युवाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन प्रशिक्षण और कोर्सेस के माध्यम से अपने कौशल को उन्नत किया है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के व्यापक स्तर पर नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।

4. मुख्य चुनौतियाँ – डिजिटल स्वरोजगार के विकास में कई बाधाएँ और चुनौतियाँ भी उपस्थित हैं। सबसे प्रमुख चुनौती इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं की असमान पहुँच है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी

भी सीमित है, और तेज ब्रॉडबैंड या वाई–फाई जैसी सुविधाएँ अक्सर उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी चुनौती डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन का कम ज्ञान है। कई युवा तकनीकी सेवाओं में सक्षम हैं, लेकिन अपने उत्पाद या सेवाओं का बाजार तैयार करने और व्यावसायिक प्रबंधन करने में अनुभवहीन हैं। इससे उनके व्यवसाय की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरी चुनौती प्रारंभिक पूंजी और सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव है। अधिकांश युवा वित्तीय संसाधनों की कमी और सरकारी योजनाओं की जानकारी न होने के कारण अपने व्यवसाय शुरू करने में बाधाओं का सामना करते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, कई युवा प्रशिक्षण, स्थानीय मार्गदर्शन और अनुभव के माध्यम से इन बाधाओं को पार करने का प्रयास कर रहे हैं।

5. सरकारी पहल और समर्थन – सरकार ने डिजिटल स्वरोजगार और उद्यमिता के विकास में विभिन्न पहल की हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया है।

डिजिटल इंडिया के प्रशिक्षण केंद्र और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवाओं को डिजिटल कौशल सिखाते हैं, जबकि स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना वित्तीय सहायता और व्यवसायिक परामर्श प्रदान करते हैं। इन पहलों के माध्यम से युवाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने, संचालन करने और विस्तार करने का अवसर मिला है। सरकारी पहल ने न केवल युवाओं में डिजिटल उद्यमिता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, बल्कि उन्हें व्यावसायिक जोखिम लेने और नए स्वरोजगार मॉडल अपनाने के लिए भी प्रेरित किया है। साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण से युवाओं को बाजार तक पहुँच, वित्तीय लेनदेन और ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन मिला है।

निष्कर्ष:

रीवा जिले में डिजिटल उद्यमिता और स्वरोजगार ने युवाओं के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव लाए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से युवाओं ने पारंपरिक रोजगार की सीमाओं को पार कर नए अवसरों की खोज की है। डिजिटल कौशल और प्रशिक्षण के विकास ने युवाओं को न केवल तकनीकी दक्षता प्रदान की है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, सशक्त और नवप्रवर्तनशील बनने का अवसर भी दिया है। विशेष रूप से, ई–कॉमर्स और तकनीकी स्टार्टअप्स जैसे स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं ने अपनी आय बढ़ाई है, सामाजिक पहचान हासिल की है और ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी समाज में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया है। डिजिटल उद्यमिता ने युवाओं में आत्मविश्वास, नवाचार की सोच और व्यवसायिक मानसिकता को भी विकसित किया है। हालांकि, इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं की असमान पहुँच, डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन में कमी, तथा प्रारंभिक पूंजी और सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव जैसे चुनौतीपूर्ण पहलू अभी भी विद्यमान हैं। इन बाधाओं के बावजूद, सरकारी पहल जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने युवाओं को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है।

समग्र रूप से, यह अध्ययन दर्शाता है कि रीवा जिले में युवाओं के लिए डिजिटल उद्यमिता और स्वरोजगार की संभावनाएँ व्यापक और मजबूत हैं। यदि उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करने का अवसर मिले, तो वे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार, डिजिटल उद्यमिता न केवल रोजगार का साधन है, बल्कि युवाओं की सामाजिक स्थिति, आत्मनिर्भरता और जीवन गुणवत्ता को सुधारने का एक सशक्त माध्यम भी बन गई है। रीवा जिले के विशेष संदर्भ में यह शोध यह स्पष्ट करता है कि युवाओं के लिए डिजिटल स्वरोजगार एक संभावनापूर्ण और टिकाऊ विकल्प है, जो उनके भविष्य और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ –

1. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम : दृष्टि एवं उद्देश्य, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2019, पृष्ठ 7–9
2. भारत सरकार, डिजिटल इंडिया : कार्यक्रम एवं प्रगति रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली, 2018, पृष्ठ 12–15
3. अमिताभ कुंडू – भारत में रोजगार और उद्यमिता, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2015, पृष्ठ 134–138
4. भारत सरकार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : दिशा–निर्देश एवं प्रभाव अध्ययन, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, 2021, पृष्ठ 41–45
5. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, स्किल इंडिया वार्षिक प्रतिवेदन, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2020, पृष्ठ 25–29
6. पंकज मेहरा – भारत में उद्यमिता विकास, मैकग्रा–हिल एजुकेशन, नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ 89–94
7. रवि सुंदरम – डिजिटल इंडिया : सामाजिक कल्पनालोक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2018, पृष्ठ 156–160
8. सुरेन्द्र कुमार – डिजिटल समाज और भारत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017, पृष्ठ 48–52
9. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टार्टअप इंडिया कार्ययोजना, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ 18–22
10. विश्व आर्थिक मंच, भविष्य के रोजगार पर प्रतिवेदन, डब्ल्यू.ई.एफ. प्रकाशन, जेनेवा, 2020, पृष्ठ 44–49